(क) क्या सरकार असम में युद्धविराम के अधीन सक्रिय किसी आतंकवादी संगठन (संगठनों) से कोई बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम और केन्द्र के साथ बातचीत में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) से (ख) : सरकार ने हिंसा का रास्ता छोड़कर भारत के संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांगे रखने के इच्छुक किसी भी समूह के साथ बातचीत करने की इच्छा हमेशा व्यक्त की है।**

**­**

 **असम में जहां इस समय यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है, वहीं परेश बरुआ के नेतृत्व में यू एल एफ ए (उल्फा) के एक गुट ने शांति प्रक्रिया का विरोध करना अभी भी जारी रखा हुआ है। इस समय त्रिपक्षीय वार्ता दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी)/एन और डी एच डी (जोएल गरसोला) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड/प्रोग्रेसिव (डी बी एफ बी-पी) के साथ चल रही है। सरकार ने शांति प्रक्रिया को तेज करने के लिए इन समूहों के साथ बातचीत करने हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत सरकार के प्रतिनिधि को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी/रंजन दाईमेरी) के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरु करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यू पी डे एस) के साथ दिनांक 25 नवंबर, 2011 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यू पी डी एस ने दिसंबर, 2011 में संगठन के रुप में स्वयं का विघटन कर दिया और इसने जनवरी, 2012 में हुए कारबी अंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव में भाग लिया। दिनांक 24 जनवरी, 2012 को असम में नौ आतंकवादी समूहों के 1695 काडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया और गुवाहाटी में केन्द्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने हथियार डाल दिए।**